30 MAR 2012

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
बि०स०प्रे०सं०...659...तिथि...20/4/12

बि० स०मु० (एल०ए०वादवृत्त) 20—मो०एल०—1,500

अध्यक्ष : प्रधान सचिव से इस की जांच करा लेंगे ।

श्री संजय सरावगी : विकास आयुक्त से करा दें या चीफ सेक्रेटरी से अध्यक्ष महोदय ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य प्रश्नकर्त्ता को आप ने हिदायत दी कि ऊंगली न दिखाईये, ताव में नहीं बोलिये, उसी तरह सं मंत्री अगर कोई ताव में बोलते हैं तो यह आप देखियेगा कि हम देखेंगे ?

अध्यक्ष : उन के लिये भी है ।

एक महीना के अंदर प्रधान सचिव से इस की जांच करायेगे और साथ ही साथ, जो क्रय में संलग्न पदाधिकारी हैं, स्टोर इंचार्ज, उस को वहां से बिरमित कर के, तब ये जांच करायेंगे

(थपथपी)

अल्प-सूचित यप्रश्न समाप्त हुआ। अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या : ३०४५ (मा०स०श्री अरूण कुमार)

श्री विजेन्द्र प्र०यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड १ : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड २ : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड ३ : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड ४ : सलखुआ प्रखंड में एक ३३/११के०वी०ए० का विद्युत उप केन्द्र निर्माणाधीन है, जिस से इस प्रखंड के विद्युतीकृत गांव को विद्युत आपूर्त्ति की जानी है । इस के ३३ के०वी०ए० लाईन के तार की चोरी होने के कारण इसे अब तक चालू नहीं किया जा सका है । चोरी गये तार को बदलकर माह मई,१२ में उप-केन्द्र चालू करने का लक्ष्य है । साथ ही, मई,२०१२ से गांव के विद्युतीकरण का काम भी प्रारंभ कर दिया जायेगा । जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत किये जा रहे कार्यो का माह जुलाई,१२ तक पूरा करने का लक्ष्य है, थोड़ी-सी वृद्धि होगी ।

श्री अरूण कुमार : माननीय मंत्री जी, खंड ३ को स्वीकारात्मक बताये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वीकार किये हैं, जून के बाद वहां विद्युतीकरण वहां नहीं होगा। इसलिये मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जून के पहले क्या हरेक पंचायत में मंत्री जी विद्युतीकरण करवाने का विचार रखते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्र०यादव,मंत्री : महोदय, ग्रामीण विद्युती करण योजना सेंट्रल स्पौंसर्ड स्कीम है राजीव गांधी विद्युतीकरण की योजना । ११वीं पंचवर्षीय योजना में केवल १०परसेंट बी०पी०एल० के लिये कभरेज एरिया रखा गया है । लेकिन अब भारत सरकार ने

स्वीकारा है, हमलोगों के जद्दोजेहाद के बाद कि १२वीं पंचवर्षीय योजना जो ०१,अप्रील से प्रारंभ हो रहा है, उस में टोटलिटी में उस प्रोजेक्ट का एडिशनल डी०पी०आर० बना रहे हैं, उस को भेज भी रहे हैं, बल्कि २० जिले का भेजा भी जा चुका है, बाकी १७ जिले का डी०पी०आर० बन रहा है और आगे भेज कर उस की स्वीकृति के बाद संपूर्ण कभरेज के एरिया को फुल-फिल किया जायेगा।

....